प्रकाशन और सूचना का प्रसार

प्रकाशन और सूचना का प्रसार

लघु उद्यमियों/उद्योगपतियों को लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए नीतियों तथा कार्यक्रमों, उपलब्ध संस्थागत सेवाओं और संगठनात्मक सुविधाओं के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए विविध प्रकार के अनेक सशुल्क और नि:शुल्क प्रकाशन प्रकाशित किए जाते हैं।

लघु उद्योग समाचार

लघु उद्योग समाचार सीडो का एक त्रैमासिक पत्र है जो लघु उद्योग क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की अद्यतन जानकारी देता है। अब यह नए रूप में एक ही कवर में अंग्रेजी तथा हिन्दी में साथ-साथ प्रकाशित किया जाता है। यह केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों, भारत सरकार के आदेशों, परिपत्रों, गजट अधिसूचनाओं, फील्ड क्रियाकलापों, लघु उद्योगों की सांख्यिकी सूचना आदि के बारे में जागरूकता का सृजन तथा सूचना का प्रसार करता है। साथ ही इसमें सम्भावी तथा विद्यमान उद्यमियों के लिए प्रेरक लेख भी होते हैं।

लघु उद्योग समाचार के पिछले कुछ अंकों ने लघु उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित व्यापक विषयों की विवेचना की है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

लघु उद्योग के 50 वर्ष	:	अंक : जनवरी-दिसम्बर 1997
सहस्राब्दि की ओर लघु उद्योग	:	अंक : जनवरी-सितम्बर 1998
लघु उद्योगों में रुग्णता	:	अंक : अक्टूबर-दिसम्बर 1998
बजट 1999-2000 में लघु उद्योग	:	अंक : जनवरी-मार्च 1999
उद्यमियों को राष्ट्रीय पुरस्कार	:	अंक : अप्रैल-जून 1999
निर्यात विशेषांक	:	अंक : जुलाई-सितम्बर 1999
लघु उद्योगों के लिए नवीन पहलें	:	अंक : अक्टूबर-दिसम्बर 1999
लघु उद्योगों पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव	:	अंक : जनवरी-मार्च 2000
लघु उद्योगों का राष्ट्रीय सम्मेलन (I)	:	अंक : अप्रैल-सितम्बर 2000
लघु उद्योगों और अति लघु क्षेत्र हेतु व्यापक नीति पैकेज	:	अंक : अक्टूबर-दिसम्बर 2000
लघु उद्योग क्षेत्र तथा संघीय बजट 2001-02	:	अंक : जनवरी-मार्च 2001
लघु उद्योगों पर राष्ट्रीय सम्मेलन तथा राष्ट्रीय पुरस्कार (II)	:	अंक : अप्रैल-सितम्बर 2001
लघु उद्योगों पर राष्ट्रीय सम्मेलन तथा राष्ट्रीय पुरस्कार	:	अंक : अक्टूबर-दिसम्बर 2001
संघीय बजट 2002-03	:	अंक : जनवरी-मार्च 2002
लघु उद्योगों पर राष्ट्रीय सम्मेलन (III)	:	अंक : अप्रैल-सितम्बर 2002
लघु और मझले उद्योग-वैज्ञानिक परिपेक्ष्य में	:	अंक : अक्तूबर-दिसम्बर 2002
संघीय बजट 2003-04 और लघु उद्योग	:	अंक : जनवरी-मार्च 2003

लघु उद्योग समाचार — **एक प्रति - 25 रुपये**

सशुल्क प्रकाशन — **वार्षिक शुल्क - 100 रुपये**

कृपया अंशदान के लिए नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली को अपना चैक/ड्राफ्ट सीधे ही इस पते पर भेजें : नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली - 110054

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में सूचना एवं सुविधा केन्द्र (आई एफ सी)

सूचना एवं सुविधा केन्द्र की स्थापना के पीछे मूल विचार लघु उद्योग संवर्धन एवं विकास के क्षेत्र में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय और सम्बन्धित संस्थानों की सेवाओं तथा क्रियाकलापों के सम्बन्ध में तुरन्त एवं सरल जानकारी प्रदान करना है। सूचना काउंटर कम्प्यूटरीकृत है तथापि और अधिक जानकारी के लिए विवरणिका, पैम्फलेट्स, पुस्तकें इत्यादि तथा सूचना की हार्ड कापी उपलब्ध कर्रवाई जाती हैं।

सम्भावी तथा विद्यमान उद्यमियों का विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के सूचना काउंटर पर तथा फील्ड संस्थानों में स्वागत है। सामान्य रूप से उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार से है :

- सम्भावी उद्यमियों को लघु उद्योग इकाई किस प्रकार स्थापित करें, इस बारे में परामर्श देना तथा सूचना प्रदान करना और उपयुक्त दिशा-निर्देश के द्वारा उन्हें सहायता देना।
- विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ तथा कार्यक्रम।
- केन्द्र सरकार की नीतियाँ।
- लघु उद्यमों से सम्बन्धित नीतियाँ तथा लघु उद्यमों के संवर्द्धन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाएँ।
- पंजीकरण योजना तथा पंजीकरण प्रपत्रों पर सूचना।
- आई डी आर अधिनियम पर सूचना तथा अधिनियम के अन्तर्गत जारी परिभाषा पर अधिसूचना।
- सरकार की ऋण नीतियाँ।
- महत्वपूर्ण संगठनों जैसे एन एस आई सी, सिडबी इत्यादि की योजनाएँ।
- पी एम आर वाई से सम्बन्धित दिशा-निर्देश और अन्य सूचना।
- परियोजना की रूपरेखा तक पहुँच।
- सरकारी विभागों द्वारा लघु उद्योगों से ही खरीदने हेतु आरक्षित मदों की सूची तक पहुँच।
- लघु उद्योगों से सम्बन्धित तकनीकी और मार्केटिंग आँकड़े, यदि उपलब्ध हों।
- लघु उद्योग क्षेत्र में ही विनिर्माण हेतु मदों की सूची।
- मुख्यालय में स्थित सूचना एवं सुविधा केन्द्र— भूमितल, गेट सं. 4 के समीप निर्माण भवन, नई दिल्ली -110011 संगठन तथा सम्बन्धित क्षेत्रों से सम्बन्धित संस्थानों की सेवाओं तथा क्रियाकलापों पर सारी जानकारी प्रदान करता है। कोई भी आगन्तुक काउंटर पर आ सकता है या दूरभाष संख्या 011-23019219 पर किसी भी कार्यदिवस को फोन करके अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंटर पर वितरण हेतु नि:शुल्क प्रकाशन भी उपलब्ध है।

इसी प्रकार, देश भर के लघु उद्योग सेवा संस्थानों में स्थित विभिन्न सूचना एवं सुविधा केन्द्रों में सामान्य जन सूचनार्थ सम्पर्क कर सकते हैं।

लघु उद्यमों की सूचना एवं संसाधन केन्द्र नेटवर्क (सीनेट)

सीनेट (लघु उद्यम नेटवर्क) परियोजना विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय का एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी पहल है। यह परियोजना मैसर्स सी एम सी लि. के सहयोग से 2 वर्षों की अवधि के साथ जून-जुलाई, 2002 में आरम्भ की गई थी। सी एम सी के लिए समय अवधि 7 तिमाहियाँ थीं, जो मार्च 2002 को समाप्त हुई। यह परियोजना अब आरम्भ हो चुकी है।

सीनेट की मान्यताएँ हैं कि

- लघु उद्यमों के लिए डाटाबेसिस बहुत ही कम एवं ना काफी हैं।
- सरकार का स्थान सूचना में सबसे बड़े उत्पादकों एवं देनेवालों में बना हुआ हैं।
- सूचना सेवाओं का प्रमुख भाग मैनुअल/असंगठित वातावरण में प्रदान किया जाता है।
- सूचना देनेवाले अलग-अलग होकर कार्य कर रहे हैं।
- सूचना विस्तीर्ण की सुविधा भली प्रकार विकसित नहीं है।

सीनेट महत्व समझती है कि

- कम्प्यूटर डाटाबेसिस सूचना प्रदान करने का सबसे कुशल एवं न्यायसंगत ढंग हैं।
- कम्प्यूटर डाटाबेसिस की शक्ति का निम्न में कोई मुकाबला नहीं है।
- सरल पहुँच एवं सम्पूर्ण जानकारी।
- पहुँच का एक ही स्रोत एवं बहुत निम्न लागत पर उपलब्धता।
- सूचना का प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए प्राय: सूचना एक निर्णायक निवेश है।
- सूचना सेवाएँ लघु उद्यमों के लिए एक महत्वपूर्ण अड़चन है।
- भारत में डाटाबेस उद्योग के लिए संवर्धन तथा निवेश की आवश्यकता है।
- लघु उद्यमों के हित में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्ज एवं डाटाबेसिस की कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता है।
- हमें लघु क्षेत्र के लिए डाटाबेसिस एवं सूचना सेवा उत्पादनों का पॉयनर, सृजन एवं संवर्धन करना चाहिए।

सीनेट के उद्देश्य

निम्न का सृजन करने के लिए

- लघु उद्योग क्षेत्र, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय उद्योग एसोसिएशनों, एन. जी. ओ. तथा उद्यमों के संवर्धन एवं विकास में प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: लगे हुए केन्द्रीय/राज्य सरकारें, अन्य केन्द्रीय/राज्य अभिकरणों, लघु एवं मध्यम उद्यमों का इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क।
- लघु उद्योग क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित सूचना प्रदान करने वालों और सूचना के इच्छुक व्यक्तियों के बीच नेटवर्क समझौते का संवर्धन करने के लिए

सीनेट के ग्राहक

सीनेट निम्न को अपने ग्राहकों के रूप में पहचानती है :

- सम्भाव्य एवं विद्यमान उद्यमी
- लघु उद्यम संवर्धन अभिकरण
- एसोसिएसन्ज
- अनुसन्धानकर्ता
- नीति तैयार करनेवाले
- विद्यार्थी

सीनेट संरचना

नेटवर्क में पहले चरण में 21 इलैक्ट्रॉनिक 'नोडल' शामिल हैं। एक मुख्य नोडल केन्द्र विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में, 5 टैक्नोलाजी नोडल केन्द्र लघु उद्योग सेवा संस्थान - कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर एवं अहमदाबाद में तथा 15 यूज़र केन्द्र लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली, गुवाहाटी, पटना, पणजी, सोलन, जम्मू, त्रिचूर, इन्दौर, कटक, लुधियाना, जयपुर, कानपुर, हैदराबाद, करनाल एवं गंगटोक में स्थापित किए गए।

मुख्य नोड के कार्य

- कुल नियन्त्रण एवं बाकी संस्थानों इत्यादि से सहयोग, संगठन और करार का कार्यान्वयन
- नेटवर्क समन्वय एवं डाटाबेसिस का संसाधन एवं भण्डारण।
- परियोजनाएँ निर्धारित करना एवं उन्हें चालू करना
- ट्रेनिंग एवं एच आर डी।
- प्रकाशन एवं डाक्यूमेंट सप्लाई सेवाएँ।

टी एन सीज के कार्य

- टैक्नोलाजी डाटावैंक्स में विशिष्टता
- क्षेत्रीय सूचना प्रलेखन केन्द्र
- पूछताछ एवं पूर्ति सेवाएँ
- प्रकाशन विस्तार

सीनेट इन्फो-डेस्क

- डाटाबेसिस
- येलो पेजिज

- प्रोजेक्ट प्रोफाइल्ज
- क्लॅस्टरज
- प्रकाशन
- डायरैक्ट्री

पब्लिकेशन्ज

- बिबलोग्राफी
- नीतियाँ एवं कार्यक्रम
- नियम एवं प्रक्रियाएँ
- पत्रिकाएँ
- परिपत्र एवं अधिसूचनाएँ
- ट्रेड रिपोर्ट्स
- सम्पूर्ण प्रपत्र

उप संविदात्मक एक्सचेंजिज

- प्रौद्योगिकी ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट्स

सीनेट की स्थिति

परियोजना के भाग के रूप में ई-मेल सम्पर्क के साथ कम्प्यूटर सुविधाएँ विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में मुख्य नोडल केन्द्र, 5 प्रौद्योगिकी नोडल केन्द्रों (लघु उद्योग सेवा संस्थान, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर एवं अहमदाबाद) तथा 15 यूजरज सेण्टरज, लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली, गुवाहाटी, पटना, पंजिम, सोलन, जम्मू, त्रिचुर, इन्दौर, कटक, लुधियाना, जयपुर, कानपुर, हैदराबाद, करनाल एवं गंगटोक में उपलब्ध कराई गईं।

परियोजना को बाद में मार्च, 2000 में संशोधित किया गया और इसे सामान्यत: संशोधित सीनेट परियोजना के रूप में जाना जाता है।

परियोजना में तीन पहलू (क) कार्यालय ऑटोमेशन (ख) सीनेट एप्लीकेशन तथा (ग) सर्वर हॉस्टिंग पर बल दिया जाता है।

ऑफिस ऑटोमेशन	सीनेट एप्लीकेशन	सर्वर हॉस्टिंग
शिकायतें कोर्ट मामले	येलो पेजिज	रिस्क सर्वर
संसदीय प्रशासन	प्रोजेक्ट प्रोफाइल	मेल सर्वर
वित्तीय लेखाकरण	कलॅस्ट्र स्टडीज	वेब सर्वर
प्रचार	फीडबैक	रेडियस सर्वर
व्यक्तिगत प्रबन्ध	कोडीफिकेशन स्कीम्ज	डाटाबेस सर्वर
प्रगति अनुश्रवण	डायरैक्ट्रीज	लीडड कानैक्टीविटी
प्रशिक्षण	इवेंट्स	आई एस डी एन माइग्रेसन
सांख्यिकी	विजिट्रज डाटाबेस	
बैठकें		
प्रलेख प्रबन्ध!		

परियोजना के भाग के रूप में बारह कार्यालय ऑटोमेशन एप्लीकेशन्ज, आठ वेब-इनेबल्ड एप्लीकेशन्ज तथा कम्प्यूटिंग इन्फरास्ट्रक्चर को आरम्भ किया गया है। आफिस ऑटोमेशन एप्लीकेशन्ज लघु उद्योग विकास संगठन में ई-गवरनेंस के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है, जबकि वेब-इनेबल्ड एप्लीकेशन्ज का उद्देश्य लघु-व्यापार को ई-सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा उन तक पहुँचना आसान बनाना है।

वेब इनेबल्ड एप्लीकेशन्ज के लिए फ्रण्ट एंड एक व्यापक ज्ञान प्रवेशद्वार है।

डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.स्मालइंडस्ट्रीइंडिया.कॉम

अथवा

डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.लघु-उद्योग.कॉम

इसका उद्घाटन तत्कालीन गृहमन्त्री श्री एल. के. आडवाणी ने 30 अगस्त, 2001 को किया था। कम्प्यूटिंग इन्फरास्ट्रक्चर में रिस्क एवं इनटेल वेसड सर्वरज तथा लीजड लाइन कनैक्टीविटी के साथ स्टेट ऑफ दी आर्ट इक्यूपमैंट हैं। सीनेट एप्लीकेशन्ज इस पोरटल के माध्यम से हॉस्ट किया जाता है। लघु उद्योग क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रयोगकर्ताओं को सूचना देने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए पोरटल को सिंगल स्टॉप स्रोस के रूप में डिजाइन किया गया है। यह अपने सम्भाव्य ग्राहकों एवं विद्यमान उद्यमियों, संघों, अनुसंधानकर्ताओं एवं विद्यार्थियों की पहचान करता है। पोरटल लघु उद्योगों पर अन्य लाभकारी स्थानों को कई हाइपर लिंक्स ऑफर करता है। यह वेब आधारित सीनेट एप्लीकेशन्ज के इन्टरफेस के साथ-साथ आई एस ओ-9000 प्रतिपूर्ति एप्लीकेशन्ज तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए ऑन लाइन इन्डेन्ट्स को प्रस्तुत करने की ट्रेकिंग भी करता है। यह प्रत्याशा की जाती है कि यह पोरटल सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वसनीय एवं सही सूचना देने के लिए इस क्षेत्र की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

21 फरवरी, 2002 को माननीय लघु उद्योग राज्य मन्त्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने सीनेट परियोजना का उद्घाटन किया और 'वैश्वीकरण एवं लघु उद्योगों पर इसका प्रभाव' पर एक ऑनलाइन चैट सत्र में भाग लिया जो पोरटल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.स्मालइंडस्ट्रीइंडिया.कॉम पर होस्ट किया गया। नेट प्रयोगकर्त्ताओं ने इस पर उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया दिखाई। लघु उद्योग राज्य मन्त्री ने विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में सीनेट केन्द्र में 16 जुलाई, 2002 को एक अन्य ऑनलाइन चैट सत्र में भाग लिया जो 'लघु उद्योग नई नौकरियों का सृजनकर्ता' विषय पर था।

सीनेट के अन्तर्गत विकसित सभी एप्लीकेशन्ज को चरणबद्ध रूप से प्रयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध किया जा रहा है। दूसरे छोर के प्रयोगकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन समर्थन आरम्भ हो चुका है।